

अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य बना झारखंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मशिन (अमृत) 2.0 हेतु झारखंड सरकार की शत-प्रतिशत योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही झारखंड पूरे देश में अमृत 2.0 के तहत योजनाओं की स्वीकृति में पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- पहले चरण में 6 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था, जिनमें झारखंड पहला ऐसा राज्य है, जिसकी सभी योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली है।
- इससे राज्य के 16 नगर निकायों- रामगढ़, समिडेगा, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, बरहरवा, बड़कीसरइया, बचरा, छतरपुर, हरहिरगंज, वंशीधर, धनवार, महगामा, डोमचांच, कपाली और वशिरामपुर की जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त होगी। इसके अलावा अमृत सटी में अपशष्टि जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य तेज़ हो सकेगा।
- झारखंड में अमृत 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्य हैं- शहरी क्षेत्र के हर घर को निःशुल्क पीने का पानी पहुँचाना, राज्य के सात प्रमुख शहरों में अपशष्टि जल प्रबंधन, सभी निकायों में जलस्रोत का जीर्णोद्धार और 2025-26 तक हरियाली वकिसति करना।
- गौरतलब है कि राज्य में हर घर में लगने वाले मीटर कनेक्शन को पहले ही निःशुल्क कर दिया गया है तथा नयितरति मात्रा में जल उपयोग करने वाले परिवार को निःशुल्क जलापूर्ति की घोषणा की जा चुकी है, चाहे वो वाटर कनेक्शन किसी भी योजना के तहत मिला हो।
- राज्य के 16 नगर निकायों में 190000 घरों को टैब वाटर के रूप में निःशुल्क जल देने की योजना है। इन योजनाओं से 900000 से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। योजनाओं में नवीन तकनीक, जैसे- स्काडा, जीआईएस और सेंसर का इस्तेमाल होगा।
- राज्य को अमृत 2.0 के तहत 1178 करोड़ रुपए केंद्र के अंशदान राशिके रूप में प्राप्त हैं। प्रथम चरण में जनि योजनाओं के लिये स्वीकृति मिली है, उनमें कुल 1122 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार का अंशदान भी है।
- उल्लेखनीय है कि नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मशिन (अमृत), देश का पहला केंद्रति राष्ट्रीय जल मशिन है, जिसि जून 2015 में देश के 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिये शुरू किया गया था।